रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062023-246775
CG-DL-E-23062023-246775

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2640] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2023/आषाढ़ 2, 1945
No. 2640] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2023/ASHADHA 2, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2023

का.आ. 2760(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों में लगी हुई सेवाओं, अर्थात्:-

(क) भारत सरकार की टकसालें, कोलकाता, नोएडा, मुंबई और हैदराबाद;

(ख) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक;

(ग) प्रतिभूति मुद्रण मुद्रणालय, हैदराबाद;

(घ) प्रतिभूति पेपर मिल, होशंगाबाद;

(ङ) बैंक नोट मुद्रणालय, देवास की सेवाएं; और

(च) करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड,

जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के क्रमश: मद 11. मद 12 [(ख) और (ग) दोनों], मद 21, मद 22 और मद 25 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाए;

और, केंद्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उक्त उद्योग को अंतिम बार भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 735(अ), तारीख 17 फ़रवरी, 2023 द्वारा 30 जनवरी, 2023 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त उद्योग की छह मास की और अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना लोकहित में अपेक्षित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त औद्योगिक उपक्रमों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 30 जुलाई, 2023 से छह मास की और अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/4/2011-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi the 23rd June, 2023

S.O. 2760(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the following industrial undertakings under the Ministry of Finance namely, the –

(a) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai and Hyderabad;

(b) India Security Press, Nashik;

(c) Security Printing Press, Hyderabad;

(d) Security Paper Mill, Hoshangabad;

(e) Services in the Bank Note Press, Dewas; and

(f) Currency Note Press, Nashik Road,

which are respectively covered under items 11, 12 [both (b) and (c)], 21, 22, and 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be public utility service for the purpose of the said Act:

And whereas the Central Government has lastly declared the said industrial undertaking to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 30th January, 2023, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 735(E), dated 17 February, 2023;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industrial undertakings for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the said industrial undertakings to be public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 30th July, 2023.

[F. No. S-11017/4/2011-IR (PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.06.23 21:53:22 +05'30'